FUNDAMENTAL RIGHTS

OF INDIAN CITISENS

भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार

FUNDAMENTAL RIGHTS

- The Fundamental Rights are enshrined in Part III of the Constitution (From Articles 12 to 35). / मौलिक अधिकार संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12 से 35) में निहित हैं।

- Part III of the Constitution is described as the Magna Carta of India.
  संविधान का भाग III भारत का "मैग्ना कार्टा" कहलाता है।

- *Magna Carta* was a Charter of Rights issued by King John of England in 1215, which was the first written document related to citizens' rights./ मैग्ना कार्टा (1215) इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर था — जो नागरिकों के अधिकारों से जुड़ा पहला लिखित दस्तावेज था।

- These Fundamental Rights were borrowed from the US Constitution (Bill of Rights).
  ये अधिकार अमेरिकी संविधान (बिल ऑफ राइट्स) से लिए गए हैं।

Originally Mentioned 7 Fundamental Rights / प्रारंभिक रूप से दिए गए 7 मौलिक अधिकार

Fundamental Right	Articles	मौलिक अधिकार
Right to Equality	14–18	समानता का अधिकार
Right to Freedom	19–22	स्वतंत्रता का अधिकार
Right Against Exploitation	23–24	शोषण के विरुद्ध अधिकार
Right to Freedom of Religion	25–28	धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
Cultural and Educational Rights	29–30	सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार
Right to Property	31	संपत्ति का अधिकार (44वें संशोधन द्वारा हटाया गया)
Right to Constitutional Remedies	32	संवैधानिक उपचार का अधिकार

44TH AMENDMENT, 1978

- In the year 1978, through 44th amendment act Right to property was deleted from the list of Fundamental Rights.
- वर्ष 1978 में, 44वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था।

- Now it is a legal right under Article 300 A in part XII of the constitution.
- अब यह संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार है।

- The number of Fundamental Rights are 6 at present day Constitution.
- वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है।

Are Fundamental Rights Justiciable?
क्या मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय हैं?

- Citizens can move the Supreme Court and other courts for the enforcement of Fundamental Rights
- नागरिक मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों में जा सकते हैं।

There are two different mechanisms for the enforcement of Fundamental Rights :

मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए दो अलग-अलग तंत्र हैं:

- Judicial Review: The court's power to review public sector bodies' actions in terms of legal and constitutional appropriateness.
- न्यायिक समीक्षा: कानूनी और संवैधानिक उपयुक्तता के संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों के कार्यों की समीक्षा करने की न्यायालय की शक्ति।

Article 13 explicitly provides for the doctrine of judicial review by stating that all laws that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void.
अनुच्छेद 13 स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का प्रावधान करता है, जिसमें कहा गया है कि सभी कानून जो किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत हैं या उसका हनन करते हैं, शून्य होंगे।

Writs: Orders issued by higher courts to lower courts or a public authority commanding the performance of a particular act. Both these remedies operate through Article 32.
रिट: उच्च न्यायालयों द्वारा निचली अदालतों या किसी विशेष कार्य के निष्पादन का आदेश देने वाले किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को जारी किए गए आदेश। ये दोनों उपाय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आते हैं।

FEATURES OF FUNDAMENTAL RIGHTS

Protected by Constitution:

- Fundamental Rights, unlike ordinary legal rights, are protected and guaranteed by the constitution of the country.

संविधान द्वारा संरक्षित:

- मूल अधिकार, सामान्य कानूनी अधिकारों के विपरीत, देश के संविधान द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत हैं।

Not Sacrosanct, Permanent, or Absolute:

- They are not sacrosanct or permanent and the Parliament can curtail or repeal them but only by a constitutional amendment act.
- They are absolute but qualified.

पवित्र, स्थायी या निरपेक्ष नहीं:

- ये पवित्र या स्थायी नहीं हैं और संसद इन्हें केवल संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ही कम या निरस्त कर सकती है।ये निरपेक्ष हैं, लेकिन अर्हताप्राप्त हैं।

FEATURES OF FUNDAMENTAL RIGHTS

Suspension of Rights:

- The rights can be suspended during the operation of a National Emergency except the rights guaranteed by Articles 20 and 21.

अधिकारों का निलंबन:

- राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को छोड़कर, अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है।

Restriction of Laws:

- Their application to the members of armed forces, paramilitary forces, police forces, intelligence agencies and analogous services can be restricted or abrogated by the Parliament (Article 33)

कानूनों पर प्रतिबंध:

- सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और समरूप सेवाओं के सदस्यों पर उनके लागू होने को संसद द्वारा प्रतिबंधित या निरस्त किया जा सकता है (अनुच्छेद 33)

ARTICLE 12

It explains the state. The state includes:
यह राज्य की व्याख्या करता है। राज्य में शामिल हैं:

- **The government and the parliament of India / भारत सरकार और भारतीय संसद**
- **The government and the state legislature / राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल**
- **All local authorities (municipalities, Panchayat Raj, District boards, etc.) / सभी स्थानीय प्राधिकरण (नगरपालिकाएं, पंचायत राज, जिला बोर्ड आदि)**
- **Other statutory and non-statutory authorities (LIC, ONGC, etc.) / अन्य वैधानिक और अवैधानिक प्राधिकरण (एल.आई.सी., ओ.एन.जी.सी. आदि)**

ARTICLE 13

- All laws that are inconsistent with or in derogation of any of the Fundamental Rights shall be void.
- सभी वे कानून जो किसी भी मौलिक अधिकार के विरुद्ध हैं या उसे हानि पहुँचाते हैं, वे शून्य (अवैध) माने जाएंगे।

RIGHT TO EQUALITY

ARTICLE 14

- Equality before law and equal protection of laws.
  विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण।
- Equality before law: The absence of any special privileges in favor of any person
  विधि के समक्ष समता: किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी भी विशेष विशेषाधिकार का अभाव।

Note: Equality before law is taken from the British Constitution.

विधि के समक्ष समता ब्रिटिश संविधान से ली गई है।

- **Equal Protection of Laws: The equality of treatment under equal circumstances.**

  विधियों का समान संरक्षण: समान परिस्थितियों में समान व्यवहार।

Note: This is taken from the US Constitution

यह अमेरिकी संविधान से लिया गया है।

ARTICLE

Prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. (Access to various places)

धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। (विभिन्न स्थानों तक पहुँच)

IMPORTANT POINT TO REMEMBER:

- **Article 15(3) : the state can make special provisions for women and children. E.g. few metro seats are reserved for women passengers**
- **अनुच्छेद 15(3): राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। उदाहरण के लिए, मेट्रो में कुछ सीटें महिला यात्रियों के लिए आरक्षित हैं।**

- **Article 15(4) : the state can make special provisions for the advancement of scheduled castes and the scheduled tribes./**
- **अनुच्छेद 15(4): राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।**

ARTICLE 16

Equality of opportunity in matters of Public employment.

सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता।

- **Article 16(4): empowers the state to make special provisions for the reservation of appointments or posts in favour of any —backward class of citizen which in the opinion of state are not adequately represented in the services of the state.**
- **अनुच्छेद 16(4): राज्य को किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिक के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है, जिसका राज्य की राय में राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।**

ARTICLE 17

- Abolishes ‘untouchability’ and forbids its practice in any form.
- यह अधिनियम 'अस्पृश्यता' को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण पर रोक लगाता है।
- Accordingly the Parliament passed Untouchability (offences) Act, 1955.
- तदनुसार, संसद ने अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 पारित किया।
- In the year 1976, this act is renamed as Civil Rights Act, 1955.
- वर्ष 1976 में, इस अधिनियम का नाम बदलकर नागरिक अधिकार अधिनियम, 1955 कर दिया गया।

ARTICLE 18

- Abolition of titles except military and academic.
- सैन्य एवं शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियों का उन्मूलन।

RIGHT TO FREEDOM (ARTICLE 19-22)

ARTICLE 19

- Protection of 6 rights / 6 अधिकारों का संरक्षण
- Right to freedom of speech and expression 19 (1)(a) (freedom of expression means the right to express one‘s opinion by words of mouth, writing, printing, picture, or in any other manner) / वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार 19 (1)(a) (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है – अपने विचारों को वाणी, लेखन, मुद्रण, चित्र या किसी भी अन्य माध्यम से व्यक्त करने का अधिकार)
- Right to assemble peacefully and without arms / शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार
- Right to form associations / संघ या संगठन बनाने का अधिकार

ARTICLE 19

- **Right to move freely throughout the territory of India** / भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार
- **Right to reside and settle in any part of the territory of India** / भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार
- **Right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business** / किसी भी व्यवसाय, व्यापार या पेशे का अभ्यास करने या उसे चलाने का अधिकार
- **Right to acquire, hold, and dispose of property (deleted through 44th amendment)** / संपत्ति प्राप्त करने, रखने और उसका निपटान करने का अधिकार (44वें संशोधन द्वारा हटाया गया)

ARTICLE 20

Protection in respect of conviction for offences.

अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण।

- **20(1) - No ex-post-facto Legislation/ कोई पूर्वव्यापी कानून नहीं**
- **20(2) - No Double Jeopardy / कोई दोहरा संकट नहीं**
- **20(3) - No Self-incrimination / कोई आत्म-दोषसिद्धि नहीं**

ARTICLE 21

- Protection of life and personal liberty./ जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा।
- No person shall be deprived of his life except according to the procedure established by law. / किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

Article 21(A) :

- Right to education (added by 86th constitutional amendment act 2002).

  शिक्षा का अधिकार (86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया)।

- It guarantees the right to free and compulsory education for children between the ages of 6 and 14. / यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है।

ARTICLE 22

Protection against arrest and detention in certain cases.

कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी से सुरक्षा।

- **Under punitive detention:** right to be informed of the grounds of arrest, consult a legal practitioner, and produce before the magistrate within 24 hours.
- **दंडात्मक नज़रबंदी के अंतर्गत:** गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी पाने, किसी कानूनी विशेषज्ञ से परामर्श करने और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार।
- **Under preventive detention:** grounds of detention should be communicated, provide an opportunity to make representation.
- **निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत:** नज़रबंदी के कारणों की जानकारी दी जानी चाहिए, और पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

RIGHT AGAINST EXPLOITATION (ARTICLE 23-24)

ARTICLE 23

- Prohibition of traffic in human beings and forced labor.
- मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध।

ARTICLE 24

- Prohibition of employment of children in factories.
- कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध।

RIGHT TO FREEDOM (ARTICLE 25-28)

ARTICLE 25

- freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion./ अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र आचरण, अभ्यास और प्रचार-प्रसार की स्वतंत्रता।

ARTICLE 26

- Freedom to manage religious affairs / धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता
  - To establish and maintain institutions for religious and charitable purposes / धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव
  - Own and acquire movable and immovable property / चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण
  - Right to administer the property / संपत्ति के प्रशासन का अधिकार

ARTICLE 27

- **Freedom for Taxation for promotion of a religion.** / किसी धर्म के प्रचार-प्रसार हेतु कर लगाने की स्वतंत्रता।
- **No person shall be compelled to pay taxes for the promotion and maintenance of any religion**/ किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के प्रचार-प्रसार और रखरखाव के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

ARTICLE 28

- **Freedom from attending religious instruction.** / धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता।
- **No religious instruction shall be provided in any educational institute wholly maintained out of state funds**/किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, जो पूरी तरह से राज्य निधि से संचालित हो, कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी।

CULTURAL AND EDUCATIONAL RIGHTS (29-30)

ARTICLE 29

Protection of interest of minorities

अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण

ARTICLE 30

Rights of minorities to establish and administer educational instructions.

शैक्षिक शिक्षा की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यकों का अधिकार।

ARTICLE 32

- remedies for enforcement of rights conferred by this part.
- इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उपाय।
- The supreme court can issue orders, directions, or writs to enforce fundamental rights.
- सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आदेश, निर्देश या रिट जारी कर सकता है।

Note: BR Ambedkar told this article as the ‘heart and soul’ of the constitution / नोट: बी.आर. अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान का 'हृदय और आत्मा' बताया था।

Habeous Corpus:

- It is an order issued by the court to a person who has detained another person, to produce the body of the latter before it. Hence this is against arbitrary detention. This can be issued to a private person or public authorities.
- यह न्यायालय द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जारी किया गया आदेश है जिसने किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया है, कि वह उस व्यक्ति का शव न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। अतः यह मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने के विरुद्ध है। यह किसी निजी व्यक्ति या सार्वजनिक प्राधिकारियों को जारी किया जा सकता है।

- **Mandamus:** (To Command) Issued to a public official asking him to perform his official duties that he has failed or refused to perform.
- **परमादेश:** (आदेश देना) किसी सार्वजनिक अधिकारी को उसके उन आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है जिन्हें वह पूरा करने में विफल रहा है या करने से इनकार कर दिया है।

- **Prohibition:** (to forbid) Issued by a higher court to a lower court or tribunal to prevent the latter from exceeding its jurisdiction or usurping a jurisdiction that it does not possess
- **प्रतिषेध:** (निषेध करना) किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण को जारी किया जाता है ताकि वह अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण न करे या किसी ऐसे अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण न करे जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

- **Certiorari:** (To be certified or to be informed) Issued by a higher court to a lower court or tribunal either to transfer case pending with the latter to it or to squash the order of the latter in a case.
- **उत्प्रेषण:** (प्रमाणित किया जाना या सूचित किया जाना) किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण को जारी किया जाता है ताकि उसके पास लंबित किसी मामले को या तो उसे स्थानांतरित किया जा सके या किसी मामले में उसके आदेश को रद्द किया जा सके।

QUO-WARRANTO: BY WHAT AUTHORITY?

It is issued by a court to enquire into the legality of claim of a person to a public office.

यह किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर दावे की वैधता की जांच करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है।

ARTICLE 33

- The Parliament is empowered to abrogate the fundamental rights of the members of armed forces, Para-military forces, police forces, intelligence agencies and other related agencies.

- संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अन्य संबंधित एजेंसियों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को समाप्त करने का अधिकार है।

ARTICLE 33

- This provides for the restriction of the fundamental rights while martial law is in force in any area within the territory of the country.

- यह देश के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है।

ARTICLE 35

The Parliament makes laws to give effect to certain specified fundamental rights shall vest only in Parliament and not in the state legislature.

संसद कुछ विशिष्ट मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाती है, लेकिन ये अधिकार केवल संसद में निहित होंगे, राज्य विधानमंडल में नहीं।

Fundamental Rights given to only people of India /

मौलिक अधिकार केवल भारत के लोगों को दिए गए हैं

Article 15, 16, 19, 29, 30

The writ jurisdiction of HC is wider than the SC.

उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय से व्यापक है।

QUESTION

Practice Time

Which among the following factors constitutes the best safeguard of liberty in a liberal democracy?

निम्नलिखित में से कौन-सा तत्व एक उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा सुनिश्चित करता है?

(a) A committed judiciary / एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका

(b) Centralization of powers / शक्तियों का केन्द्रीकरण

(c) Elected government / निर्वाचित सरकार

(d) Separation of powers / शक्तियों का विभाजन

IAS PRE (2021)

QUESTION

Practice Time

Which of the following is correct?

निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

(a) The Nehru report (1928) had advocated the inclusion of Fundamental Rights in the Constitution of India.

नेहरू रिपोर्ट (1928) ने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने की सिफारिश की थी।

(b) The Government of India Act 1935 referred to Fundamental Rights.

भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया था।

(c) The August Offer, 1940, included the Fundamental Rights.

अगस्त प्रस्ताव, 1940 में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था।

(d) The Cripps Mission 1942 referred to Fundamental Rights.

क्रिप्स मिशन, 1942 ने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया था।

UPPCS MAINS 2009

QUESTION

Practice Time

In which article of the Constitution 'Equal Protection of Law' is provided?

संविधान के किस अनुच्छेद में 'कानून के समान संरक्षण' का प्रावधान है?

(a) 12

(b) 13

(c) 14

(d) 15

Chhattisgarh PCS 2018

QUESTION

Practice Time

Under which amendment act was the reservation in promotion for the scheduled castes and scheduled tribes ensured by inserting clause '4A' in Article 16?

किस संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 16 में '4A' उपबंध जोड़कर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया?

(a) 75th Amendment Act, 1994/75वाँ संशोधन अधिनियम, 1994

(b) 76th Amendment Act, 1994/76वाँ संशोधन अधिनियम, 1994

(c) 77th Amendment Act, 1995/77वाँ संशोधन अधिनियम, 1995

(d) 108th Amendment Act, 2008/108वाँ संशोधन अधिनियम, 2008

Jharkhand PCS 2023

QUESTION

Practice Time

Untouchability is abolished by which article of the Indian Constitution?

अस्पृश्यता को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा समाप्त किया गया है?

(a) 14

(b) 15

(c) 17

(d) 22

69th BPSC 2023

QUESTION

Practice Time

How many fundamental rights were provided originally by the Indian Constitution in 1950?

भारतीय संविधान में 1950 में प्रारंभिक रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे?

(a) Seven / सात

(b) Nine / नौ

(c) Five / पाँच

(d) Six / छह

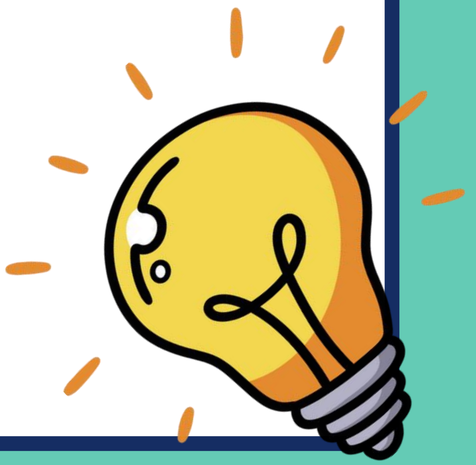

SSC CPO 04/10/23

QUESTION

Practice Time

What is the purpose of Cultural and Educational Rights?

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है?

(a) To promote a particular religion / किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देना

(b) To protect the language, culture, and religion of the minority communities / अल्पसंख्यक समुदायों की भाषा, संस्कृति और धर्म की रक्षा करना

(c) To protect the majority community / बहुसंख्यक समुदाय की रक्षा करना

(d) To prevent exploitation / शोषण को रोकना

SSC MTS 13/09/23

QUESTION

Practice Time

Which of the following is enforceable by the Indian Constitution?

निम्नलिखित में से कौन-सा भारतीय संविधान द्वारा प्रवर्तनीय है?

(a) Preamble / प्रस्तावना

(b) Fundamental Rights / मौलिक अधिकार

(c) DPSP / राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत

(d) Fundamental Duties / मौलिक कर्तव्य

SSC CHSL 02/08/23

QUESTION

Practice Time

Data Protection Bill 2021 ensures which Fundamental Right?

डेटा संरक्षण विधेयक 2021 किस मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करता है?

(a) Right to education / शिक्षा का अधिकार

(b) Right to information / सूचना का अधिकार

(c) Right to freedom of speech / अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार

(d) Right to privacy / निजता का अधिकार

SSC MTS 19/05/23

QUESTION

Practice Time

The foremost right among Rights to Freedom is —

स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन-सा है?

(a) Right to life and personal liberty / जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

(b) Preventive detention / निरोधात्मक नजरबंदी

(c) Freedom to assemble / एकत्र होने की स्वतंत्रता

(d) Right to freedom of speech and expression / वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार

SSC CGL 01/12/22

QUESTION

Practice Time

Which minorities are mentioned in Article 30 of the Indian Constitution?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है?

(a) Linguistic and religious / भाषाई और धार्मिक

(b) Religious, cultural and linguistic / धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई

(c) Cultural and linguistic / सांस्कृतिक और भाषाई

(d) Religious and cultural / धार्मिक और सांस्कृतिक

SSC CGL 08/12/2022

QUESTION

Practice Time

Which of the following cases come under the jurisdiction of the High Court and the Supreme Court?

निम्नलिखित में से कौन-से मामले उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं?

(a) Disputes between the Centre and the States / केंद्र और राज्यों के बीच विवाद

(b) Disputes among the States / राज्यों के बीच विवाद

(c) Enforcement of Fundamental Rights / मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन

(d) Protection from violation of the Constitution / संविधान के उल्लंघन से सुरक्षा

SSC CHSL 02/08/23

QUESTION

Practice Time

Which of the following articles of the Constitution of India deals with freedom of the press?

भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है?

(a) Article-19 / अनुच्छेद-19

(b) Article-20 / अनुच्छेद-20

(c) Article-21 / अनुच्छेद-21

(d) Article-22 / अनुच्छेद-22

SSC MTS 19/05/23

QUESTION

Practice Time

Which of the following is the true right of citizens regarding freedom?

निम्नलिखित में से कौन-सा नागरिकों का स्वतंत्रता से संबंधित सही अधिकार है?

(a) Freedom to assemble with arms / हथियारों के साथ एकत्र होने की स्वतंत्रता

(b) Freedom to conspire against the government / सरकार के खिलाफ साजिश करने की स्वतंत्रता

(c) Freedom of speech and expression of opinion / भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

(d) Freedom to travel abroad / विदेश यात्रा की स्वतंत्रता

SSC CGL 01/12/22

QUESTION

Practice Time

Freedom of the press is inherent in which right?

प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है?

(a) Equal protection of laws / कानूनों के समान संरक्षण का अधिकार

(b) Freedom of speech / वाक् स्वतंत्रता

(c) Freedom to form associations / संघ बनाने की स्वतंत्रता

(d) Security of work and material / कार्य और सामग्री की सुरक्षा

SSC CGL 08/12/2022

QUESTION

Practice Time

In which country were the fundamental rights first given constitutional recognition?

किस देश में सबसे पहले मौलिक अधिकारों को संवैधानिक मान्यता दी गई थी?

(a) India / भारत

(b) United States of America / संयुक्त राज्य अमेरिका

(c) France / फ्रांस

(d) Britain / ब्रिटेन

SSC CHSL 02/08/23

QUESTION

Practice Time

Which of the following is the true right of citizens regarding freedom?

निम्नलिखित में से कौन-सा नागरिकों का स्वतंत्रता से संबंधित सही अधिकार है?

(a) Freedom to assemble with arms / हथियारों के साथ एकत्र होने की स्वतंत्रता

(b) Freedom to conspire against the government / सरकार के खिलाफ साजिश करने की स्वतंत्रता

(c) Freedom of speech and expression of opinion / भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

(d) Freedom to travel abroad / विदेश यात्रा की स्वतंत्रता

SSC MTS 19/05/23

QUESTION

Practice Time

Which of the following cases come under the jurisdiction of the High Court and the Supreme Court?

निम्नलिखित में से कौन-से मामले उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं?

(a) Disputes between the Centre and the States / केंद्र और राज्यों के बीच विवाद

(b) Disputes among the States / राज्यों के बीच विवाद

(c) Enforcement of Fundamental Rights / मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन

(d) Protection from violation of the Constitution / संविधान के उल्लंघन से सुरक्षा

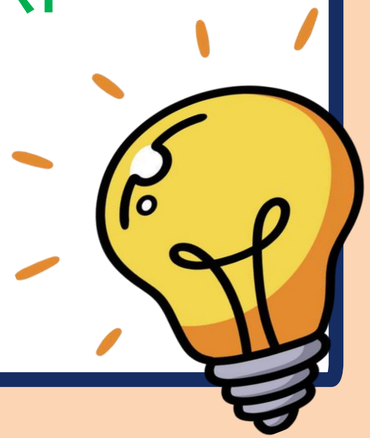

SSC CGL 01/12/22

QUESTION

Practice Time

Who is the guardian of fundamental rights under the Indian Constitution?

भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है?

(a) Parliament / संसद

(b) President / राष्ट्रपति

(c) Judiciary / न्यायपालिका

(d) Cabinet / मंत्रिमंडल

SSC CGL 08/12/2022

QUESTION

Practice Time

Which of the following Fundamental Rights was amended as a result of the decision of the Indian Supreme Court in the case of 'State of Chennai vs Champakam Dorairajan'?

'State of Chennai vs Champakam Dorairajan' मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार में संशोधन किया गया था?

(a) Right to equality before law / कानून के समक्ष समानता का अधिकार

(b) Right against discrimination / भेदभाव के विरुद्ध अधिकार

(c) Right against untouchability / अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार

(d) Right to freedom of thought and expression / विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार

SSC CHSL 02/08/23

QUESTION

Practice Time

Fundamental rights are called fundamental because they–

मौलिक अधिकारों को मौलिक कहा जाता है क्योंकि वे–

(a) are enforceable by the courts / न्यायालयों द्वारा लागू किए जा सकते हैं

(b) are in accordance with the United Nations Declaration of Human Rights / संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा के अनुरूप हैं

(c) are not easily amendable / आसानी से संशोधित नहीं किए जा सकते

(d) are natural and irrevocable rights of humans / मनुष्यों के प्राकृतिक और अविच्छेद्य अधिकार हैं

SSC MTS 19/05/23

QUESTION

Practice Time

Which part of the Indian Constitution has been called the most supernatural part by Dr. Bhimrao Ambedkar?

भारतीय संविधान के किस भाग को डॉ. भीमराव अंबेडकर ने सबसे अलौकिक भाग कहा है?

(a) Part I / भाग I

(b) Part II / भाग II

(c) Part III / भाग III

(d) Part IV / भाग IV

SSC CGL 01/12/22

QUESTION

Practice Time

In how many articles in Part III of the Indian Constitution, the Fundamental Rights are described?

भारतीय संविधान के भाग III में कितने अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है?

(a) 21

(b) 22

(c) 23

(d) 24

SSC CGL 08/12/2022

QUESTION

Practice Time

Answer Key:

1.	D
2.	A
3.	C
4.	C
5.	C
6.	A
7.	B
8.	B
9.	D
10.	D
11.	A
12.	C
13.	A
14.	C
15.	B

16.	B
17.	C
18.	C
19.	C
20.	B
21.	A
22.	C
23.	D

SSC CGL 08/12/2022

THANK
YOU